बिहार सरकार
मुख्यमंत्री का कार्यालय
(जनसंपर्क कोषांग)
प्रेस विज्ञप्ति

संख्या–cm- 61
27/01/2020

प्रत्येक व्यक्ति के मन में पढ़ाई के साथ–साथ जल संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने की अवधारणा पैदा होनी चाहिए :– मुख्यमंत्री

पटना, 27 जनवरी 2020 :– मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अधिवेशन भवन में आयोजित कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। बी0एस0ई0बी0 के अध्यक्ष श्री आनंद किशोर ने मुख्यमंत्री को पौधा भेंटकर उनका अभिनंदन किया। बिहार के विभिन्न प्रमंडलीय मुख्यालयों– पटना, गया, मुंगेर, सहरसा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा में 163.55 करोड़ रूपये की लागत से बने परीक्षा भवनों सह क्षेत्रीय कार्यालयों एवं 10.73 करोड़ रूपये की लागत से बने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के प्रशासनिक भवन का रिमोट के माध्यम से मुख्यमंत्री ने शिलापट्ट का अनावरण कर उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने 4.49 करोड़ रूपये की लागत से बी0एस0ई0बी0 के ई0आर0पी0 (इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग) सिस्टम का शुभारम्भ, 7.97 करोड़ रूपये की लागत से बी0एस0ई0बी0 के नवनिर्मित डाटा सेंटर का उद्घाटन एवं राज्य के मैट्रिक तथा इंटर के परीक्षार्थियों और शिक्षकों हेतु बनाये गये बी0एस0ई0बी0 मोबाइल एप्प को माउस क्लिक कर लांच किया। राज्य के सभी जिलों के विद्यार्थियों हेतु बी0एस0ई0बी0 क्विज प्रतियोगिता एवं बी0एस0ई0बी0 ओलंपियाड प्रतियोगिता (राउंड–2) के लोगो का अनावरण कर मुख्यमंत्री ने इसका शुभारंभ किया। शुभारंभ समारोह में बी0एस0ई0बी0 से जुडी योजनाओं एवं विद्यार्थियों को दी जा रही सुविधाओं से संबंधित लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गयी।

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बी0एस0ई0बी0 के 7 योजनाओं का शुभारंभ एवं उद्घाटन हुआ है, इसके लिए मैं शिक्षा विभाग एवं बी0एस0ई0बी0 को विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। इस अवसर पर आज मुझे काफी प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा सुधार की दिशा में कई काम किये गये हैं ताकि अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल जाने का अवसर मिल सके। टेक्नोलॉजी के विकास से परिस्थितियाँ काफी बदल गयी हैं। बिहार में 12.5 प्रतिशत बच्चे स्कूलों से बाहर थे। बच्चों को स्कूलों तक पहुंचाने के लिए हमने वर्ष 2006 से काम प्रारंभ किया और इस दिशा में पहल करते हुए वर्ष 2007 से हमलोगों ने मिडिल स्कूल की लड़कियों के लिए पोशाक योजना की शुरुआत की। इसके कारण न सिर्फ स्कूलों में लड़कियों की संख्या बढ़ी बल्कि गाँव की स्थिति और वहां का दृश्य भी बदल गया। पोशाक योजना को विस्तार देते हुए हमलोगों ने इसे पहली कक्षा से 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए लागू कर दिया। इसके बाद 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए साइकिल योजना की शुरुआत की गयी। इससे लड़कियों का मनोबल ऊँचा हुआ और लोगों की मानसिकता में परिवर्तन आया। 3 से 4 लाख शिक्षकों का नियोजन किया गया। 26 हजार से भी ज्यादा प्राथमिक विद्यालय एवं नई कक्षाओं का निर्माण कराया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार बोर्ड की परीक्षा में कई प्रकार की खामियां, कमजोरियां और भ्रष्टाचार की शिकायतें देखने को मिलीं। मैट्रिक परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र की इमारत के हर फ्लोर पर कदाचार कराते लोग देखे गये थे। नई टेक्नोलॉजी को अपनाकर

कदाचारमुक्त परीक्षा, कॉपी की जांच एवं परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने की कवायद शुरू हुई जिसके बाद परिस्थितियां बदल गयी। अब बी0एस0ई0बी0 द्वारा न सिर्फ कदाचारमुक्त परीक्षा का आयोजन कराया जा रहा है बल्कि समय सीमा के अंदर मैट्रिक और इंटर परीक्षा का परिणाम भी घोषित किया जाने लगा है। मुझे पूरा भरोसा है कि स्थिति में और अधिक सुधार होगा। आज स्थिति यह है कि यहाँ के कामों को देखने बाहर से लोग बिहार आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि नई टेक्नोलॉजी के सहारे जो काम हो रहे हैं, वह पूरी मजबूती और पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए ताकि गड़बड़ी या उसके दुरूपयोग की कोई गुंजाइश नहीं रहे। आज जिस तरह से पोर्न साइट्स के जरिये समाज में गंदगी फैल रही है, टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसा काम किया जाय ताकि गंदी चीजों को हटाया जा सके। पोर्न साइट्स पर किसी प्रकार से रोक लगनी चाहिए। लोगों को कितना भी प्रशिक्षित कर दीजिये या कोई भी कानून बना दीजिये लेकिन कुछ लोगों को गड़बड़ी पैदा करने की आदत होती है इसलिए सही ढंग से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी या समाज में गंदगी का प्रसार नहीं हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हमलोगों को काम करने का मौका मिला उस समय बिहार में परिवार का औसत प्रजनन दर 4.3 था जो अब घटकर 3.2 हो गया है। एक अध्ययन में यह पता चला कि अगर पति–पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो देश और बिहार का औसत प्रजनन दर 2 है लेकिन अगर पत्नी इंटर पास है तो देश का प्रजनन दर 1.7 है, जबकि बिहार का औसत प्रजनन दर 1.6 है। इसके बाद प्रत्येक पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया। अब तक 6000 पंचायतों में यह खुल चुका है और शेष जगहों पर इस वर्ष के अप्रैल माह तक 9वीं कक्षा की पढ़ाई प्रारंभ हो जायेगी। जल्द से जल्द शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए, इसके लिए शिक्षक नियोजन का काम भी शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि माध्यमिक विद्यालयों के साथ ही उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया हो सके इसके लिए शिक्षा विभाग के साथ मिलकर काम करें। बी0एस0ई0बी0 ने राज्य के सभी सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एक कम्प्यूटर, एक प्रिंटर के अलावा विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्णय किया है। इन सभी कामों पर 60 से 70 करोड़ रूपये का खर्च आएगा। उन्नयन बांका कार्यक्रम को विस्तार देते हुए अब इसे पूरे बिहार में 9वीं एवं 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए किया जा रहा है लेकिन इसे 11वीं एवं 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी करना लाभप्रद होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पटना में 25,000 परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा भवन तैयार होगा, इसके लिए साइट विजिट किया गया है और जमीन का आवंटन भी हो चुका है। वहां एक एकड़ में तालाब है, जहाँ हरियाली का काम किया जाएगा ताकि बड़ी संख्या में आने वाले परीक्षार्थी तालाब के इर्द–गिर्द बैठकर भी अपना समय व्यतीत कर सकें। इससे जल संरक्षण के साथ ही परीक्षार्थी हरियाली के प्रति भी प्रेरित होंगे। डी0पी0आर0 बनाकर इसी साल इसका काम प्रारंभ हो जाएगा। बिहार म्यूजियम, बापू सभागार, सभ्यता द्वारा, ज्ञान भवन, पुलिस मुख्यालय की तरह बी0एस0ई0बी0 का परीक्षा भवन भी देश का यूनिक भवन होगा। इसके बन जाने से बी0एस0ई0बी0 द्वारा आयोजित परीक्षाओं के अलावा देश भर में जितनी तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उसमें काफी सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि बिहार के हर जिले में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, जी0एन0एम0 संस्थान, महिला आई0टी0आई0, पारा मेडिकल संस्थान और हर सब डिवीजन में आई0टी0आई0 और ए0एन0एम0 स्कूल की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान आदि का निर्माण कराया गया ताकि मजबूरी में उच्च शिक्षा के लिये बिहार के बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े। समाज सुधार की दिशा में किये गये कामों एवं चलाए जा रहे

अभियानों में शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 21 जनवरी 2017 और 21 जनवरी 2018 के बाद इस वर्ष 19 जनवरी को बाल विवाह, दहेज प्रथा के खिलाफ और जल–जीवन–हरियाली अभियान एवं नशामुक्ति के पक्ष में बनी मानव श्रृंखला में 5 करोड़ 18 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर 18 हजार किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर दुनिया को यह संदेश दिया कि बिहार के लोग जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए दृढ संकल्पित हैं। हर बार बनी मानव श्रृंखला में शिक्षा विभाग ने अपनी महती भूमिका निभाई है। जलवायु परिवर्तन के प्रति महिलाओं एवं नई पीढ़ी में भी काफी जागृति आई है। हम तो कहेंगे कि इस साल बनी मानव श्रृंखला के दौरान पूरे बिहार में खींची गयी तस्वीर को संग्रहित करके उसे रिलीज करवा दें ताकि इस विषय में रूचि रखने वाले लोगों को बिहार के हर हिस्से से ली गयी मानव श्रृंखला की तस्वीरें आसानी से उपलब्ध हो सके। हम सभी के जीवन संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। पढ़ाई के साथ–साथ प्रत्येक व्यक्ति के मन में जल संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने की अवधारणा पैदा होनी चाहिए, इससे जीवन सुरक्षित रहेगा।

समारोह को शिक्षा मंत्री श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग श्री आर0के0 महाजन एवं बी0एस0ई0बी0 के अध्यक्ष श्री आनंद किशोर ने भी संबोधित किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा, बिहार राज्य शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक श्री संजय कुमार सिंह, प्राथमिक शिक्षा के निदेशक श्री रंजीत सिंह सहित बी0एस0ई0बी0 से जुड़े अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे।

कार्यक्रम के पश्चात पत्रकारों द्वारा कल जदयू की होने वाली बैठक के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कल कोई मीटिंग नहीं है बल्कि ट्रेनर्स को बुलाया गया है जो कार्यकर्ताओं को ट्रेंड करेंगे। ट्रेनर्स को टास्क देकर उसका को–आर्डिनेशन जिलों में जिलाध्यक्षों, प्रकोष्ठ अध्यक्षों, एम0एल0ए0 और एम0पी0 से कराया जाएगा ताकि ट्रेनिंग का काम तय समय–सीमा के अंदर पूरा हो सके। कोई निर्णय लेने या किसी विषय पर चर्चा करने के लिए कल की बैठक नहीं है।

******